3529. [*Transferred to 27th August, 1993*]

उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल के डिपो और उचित दर दुकानें

3530. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पास मिट्टी के तेल के डिपो और उचित दर दुकानों का आवंटन करने के लिए कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं;

(ख) इस संबंध में जिला-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन मामलों को कब तक निपटाये जाने की संभावना है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि

2531. **श्री अजीत जोगी :**
चौधरी हरि सिंह :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छदम कृषक आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं, जैसा कि 7 फरवरी, 1992 के, "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार सही और छदम कृषकों के बीच अन्तर करने के लिये कोई कदम उठायेगी ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) यह मंत्रालय 7 जनवरी, 1992 के हिन्दुस्तान टाइम्स में परोक्षी किसानों के बारे में छपी रिपोर्ट से वाकिफ है । खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में विभिन्न कारणों से बाधा पहुंची है, जिनमें किसानों द्वारा अपनी आवश्यकता की तुलना में इन वस्तुओं को बड़ी अधिक मात्रा में रोक लेना भी शामिल है । इस तरह की गतिविधि सामान्य मांग व आपूर्ति–प्रबंध में असंतुलन पैदा करती है । इस मंत्रालय को परोक्षी किसानों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के बारे में कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं । तथापि, सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित सीमाओं के भीतर नियंत्रित रखने के लिये वचनबद्ध है । आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा अन्य इसी प्रकार के कानूनों के तहत सख्त कार्यवाही की जा रही है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि वे इन कानूनों का इस्तेमाल उन व्यक्तियों के विरुद्ध करें जो समाज–विरोधी गतिविधियों, जिसमें जमाखोरी व चोरबाजारी आदि शामिल हैं, में लगे हैं ।

State of Public Distribution system in Kutch District

3532. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:
SHRI GOPALSINH G. SOLANKI:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) what is the number of fair price shops at present under Public Distribution System in Kutch District of Saurashtra region of Gujarat;

(b) whether equal number of consumers are duly registered with each of the fair price shops;

(c) what is the actual number of ration cards allotted to each shop;

(d) what is the average monthly quota of foodgrains item-wise, allocated under the PDS in the district;

(e) whether consumers have been getting their prescribed quota during the last six months;

(f) if not, what are the reasons therefor; and

(g) whether Government propose to increase the quantity of supply of each item to the fair price shops to ensure availability thereof for card holders throughout the month?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) 509.

(b) No, Sir. Number of cards attached to each of the Fair Price Shops depends upon the jurisdiction of the Fair Price Shop and hence number to consumer vary from shop to shop.

(c) The actual number of ration cards differs from shop to shop. However, average ration cards per shop come to 656.

(d) Average monthly allocation is 2500 MT wheat, 1200 MT rice, and 502.2 MT sugar.

(e) Yes, Sir.

(f) Does not arise.

(g) State Government of Gujarat has reported that since sufficient quota is allocated, no increase of quota is contemplated.

Supply of essential commodities to Arunachal Pradesh under PDS

3533. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) what is the annual-quota fixed for various essential commodities distribution through PDS for the State of Arunachal Pradesh; and

(b) what is the actual release of quota to Arunachal Pradesh itemwise during the last six months upto June, 1993?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) Bulk allocations of wheat, rice, sugar, edible oils, kerosene and soft coke are made on a month to month basis.

The allocation and lifting figures for Arunachal Pradesh from January, 1993 to June, 1993 is given in the Annexure.

[*See* Appendix CLXVIII, Annexure No. 49]

3534. [*Transferred to 26th August*, 1993]

Public Distribution System in Darjeeling

3535. SHRI RATNA BAHADUR RAI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBNTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to set up more fair price shops of M.R. shops